राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक : बैंक ऑफ इंडिया

50वीं एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 12.02.2015

स्थान - होटल रैडिसन ब्लू , रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 50वीं बैठक का आयोजन दिनांक 12 फरवरी 2015 को रांची स्थित होटल रैडिसन ब्लू में किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री रघुवर दास ,माननीय मुख्य मंत्री झारखंड ने किया । बैठक में श्री सी पी सिंह,माननीय शहरी विकास मंत्री झारखंड सरकार, श्री राजीव गौबा, मुख्य सचिव,झारखंड सरकार, श्री आर एस पोद्दार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त,श्रीमती मृदुला सिन्हा,प्रधान सचिव,संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखंड सरकार,श्री मिहिर कुमार, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार, श्री सौरभ सिन्हा,मुख्य महाप्रबन्धक,भारतीय रिजर्व बैंक, श्री के सी पांडा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री एन एन सिन्हा - मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अन्य मुख्य सचिव, सचिव, झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ कार्यपालक, झारखण्ड राज्य स्थित बैंकों के नियंत्रक प्रमुख , झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संलग्नक 1 में बैठक के सहभागियों की सूची संलग्न है।

प्रारंभ में, श्री जैन भूषण, महाप्रबंधक, एस एल बी सी ने प्रार्थना के बाद अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत किया। उन्होने स्वर्ण जयंती एस एल बी सी सभा के महत्व एवं अपेक्षाओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की।

तत्पश्चात उपस्थित तमाम अथितियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का संचालन श्री आलोक प्रकाश यादव, उप महाप्रबन्धक, एस एल बी सी ने किया । गणमान्य अतिथियों का स्वागत बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया।

<u>स्वागत भाषण</u> <u>Welcome Address:</u>

श्री राजीव सक्सेना, मुख्य महाप्रबंधक,बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय , ने अपने उदघाटन भाषण के दौरान सभी अतिथियों एवं सहभागियों को 50वीं बैठक की शुभकामना देते हुए कहा कि हमें राज्य के विकास हेतु सतत् प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की जिम्मेदारी को सफलता पूर्वक निभाते हुए, इसे आसमान की ऊचाईयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभा के सामने समस्त बैंकों एवं सहयोगियों से संबंधित समस्त मुद्दों को प्रस्तुत किया। उन्होंने निम्न मुद्दो पर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत्त कुल 2667951 खाते खोले गए है और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है हालांकि इन समस्त खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी नही किया गया है। अब तक के प्राप्त आंकड़ो के अनुसार मात्र 1748697 खातों में ही रुपे कार्ड जारी किया गया है। खोले गए खाता और जारी किए गए रुपे कार्ड में भारी अंतराल है।	समस्त सहयोगी बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन सुनिश्चित करें	समस्त बैंक
ii) रुपे कार्ड धारकों को उसके उचित उपयोग हेतु जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है	समस्त बैंक बैठक में लिये गये निर्णय पर अनुपालन सुनिश्चित करें	समस्त बैंक
iii) राज्य में बी एस एन एल का कमजोर कनेक्टिविटी, सुदूर क्षेत्रों में बिजली का नही होना एवं विशेषकर वामपंथी अतिवादी प्रभावित क्षेत्र में कमजोर कानून व्यवस्था प्रधान मंत्री जन धन योजना को लागू करने में बाधक है।	समस्त सहयोगी बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन सुनिश्चित करें	झारखण्ड सरकार/समस्त बैंक बी.एस.एन.एल
iv) बी सी/बी सी ए को हैंड-होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करना एवं उनका नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करना ताकि फिक्सड लोकेशन बी सी/बी सी ए की निरंतरता रह सके ।	सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख इस क्षेत्र में की गई प्रगति का सुक्ष्म निगरानी करें एवं सुनिश्चित करें कि शाखा स्तर पर वास्तविक कार्य हो	समस्त बैंक
v) <u>अन्य चुनौतिया :</u>		

a) **वार्षिक ऋण योजना 2014-15 में कुल रू 12324.30 करोड़ की ऋण वितरण किया गया, जिसमे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कुल रू.5710.89 करोड़ बैंक ऋण का वितरण हुया, यह लक्ष्य से काफी दूर है और अब तक इस क्षेत्र में लक्ष्य का मात्र 38.50 प्रतिशत की उपलब्धि हो पाई है। जब की कृषि क्षेत्र में यह उपलब्धि मात्र 29.86% ही है,परन्तु पिछले साल की अपेक्षा में , इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह तक कृषि क्षेत्र में रू 219.25 करोड़ ज्यादा ऋण दिया गया |** **श्री सक्सेना ने ACP 2014-15 के तहत , सभी बैंकों को ऋण-वितरण में तेजी लाने का सलाह दिया |**	**सभी बैंक वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निवेश क्रेडिट को बढाने के अतिरिक्त कृषि ऋण को बढ़ाने के लिए फसल के बुबाई के दौरान कृषि ऋण को बढ़ाए**	**समस्त बैंक**
b) **मौजूद स्वयं सहायता समूहों की तुलना में स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बहुत ही कम है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किये जाने की आवश्यकता है।**	**सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख यह निगरानी रखें कि सभी योग्य एस.एच.जी का शाखा में क्रेडिट लिंकेज किया जा सके**	**समस्त बैंक**
c) **राज्य में 24 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें मात्र 02 स्थान के लिए निर्माण कार्य**	**सभी केन्द्र में प्राथमिकता आधार पर भवन निर्माण**	**भारतीय स्टेट बैंक/बैंक ऑफ**

शुरू हुआ है। इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण के गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।	का कार्य शुरू किया जाए। प्रायोजक बैंक के नियंत्रक प्रमुख इस विषय पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें।	इंडिया/इलाहाबाद बैंक/पी एन बी/कैनरा बैंक/झारखण्ड सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय
d) राज्य में एन पी ए खातों से वसूली एक गंभीर मामला है। वसूली हेतु सरकार की मदद की आवश्यकता है। मामलों की तुरंत निपटान हेतु प्रत्येक जिला में समर्पित सर्टिफिकेट ऑफिसर पदस्थ किये जाने की आवश्यकता है। सरकार से अनुरोध है कि इस गैप को तत्काल प्रभाव से पाटने की कृपा करे। जिला स्तर पर उपायुक्तों के पास Sarfaesi Act के तहत अनादायी ऋण में बंधिकृत सम्पत्ति आदि का Seizing हेतु प्रशासनिक अनुमति प्राप्ति हेतु लंबित आवेदनों का तुरंत निपटारा का आबश्यकता पर ध्यान दिया जाय |	राज्य सरकार से प्रत्येक जिला में समर्पित सर्टिफिकेट ऑफिसर की तैनाती करने में तेजी लाने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर सरफैसी के मामले में समुचित कार्रवाई हेतु सक्रिय सहायता प्रदान करने के लिए, उपायुक्तों को झारखण्ड सरकार द्वारा समुचित दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।	ई एफ & पी आई विभाग, झारखण्ड सरकार
e) यद्यपि की राज्य का ऋण - जमा अनुपात 61.76 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है लेकिन ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र में ऋण -जमा अनुपात क्रमश: 34.83 प्रतिशत एवं 32.91 प्रतिशत है जो शहरी क्षेत्र के 63.19 प्रतिशत से काफी कम है ।	समस्त बैंक बैठक में लिये गये निर्णय पर अनुपालन सुनिश्चित करें	सभी बैंक
f) कृषि क्षेत्र में ऋण का संवितरण कम है	राज्य सरकार से अनुरोध है कि सिचाई, जल संरक्षण, सिड कल्चर एवं प्रखण्ड के द्वारा विस्तार सेवाएं प्रदान कर एकल फसल को बहू फ़सली व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाए।	राज्य सरकार / सभी बैंक

g) राज्य में फोरेक्स कारोबार कम है । निर्यात वित्तीयन प्रदान करने वाली कैटेगरी - बी अधिकृत डीलर शाखाओं की संख्या बहुत ही कम है	समस्त सहयोगी बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन सुनिश्चित करें	राज्य सरकार एवं समस्त बैंक

एस एल बी सी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक ने समस्त हितधारकों से राज्य सरकार के विकास कार्यो में सहयोग हेतु अनुरोध किया। SLBC द्वारा तैयार किया गया - " झारखण्ड के समेकित विकास के लिये बैंकिंग की विस्तृत कार्य योजना एवं सुझाव" के लोकार्पण पर अपनी खुशी ज़ाहिर किया | उनहोंने बैंकों द्वारा राज्य के समेकित विकास में , अपनी भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर किया

<u>श्री मिहिर कुमार - निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का संबोधन</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 50वीं बैठक की हार्दिक बधाई के साथ अपना संबोधन शुरू करते हुए श्री कुमार ने कहा प्रधान मंत्री जन धन योजना के 05 स्तंभों के बारे में चर्चा करते हुए कहा की यह योजना राज्य के विकास के लिए अहम होगा। उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1. प्रधानमंत्री जन धन योजना - प्रधानमंत्री जन धन योजना के 05 स्तम्भ है - 1. ग्राहकों का बैंक तक पहुँच (Accesibility) 2. बैंक मित्र 3. प्वाईंट ऑफ सेल मशीन एवं माइक्रो ए टी एम 4.इन बिल्ट ओवर ड्राफ्ट प्रदान करना 5. पेंशन एवं सुरक्षा उन्होंने एस एल बी सी से निम्न आग्रह किया : - a) बी सी/बी सी ए की उपलब्धता का	-- समस्त बैंक इसके कार्यान्वयन हेतु संभावित कार्रवाई करें	समस्त बैंक

ध्यान रखा जाए **b) बैंक इन खातों को जीवित रखने के साथ -साथ बैंक लोगों को खाते में उपलब्ध राशि का भुगतान करें ।**		

श्रीमती मृदुला सिन्हा,प्रधान सचिव,संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखंड सरकार का संबोधन :

राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता पर सभी बैंकों को हार्दिक बधाई दिया एवं सरकार के योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका पर अपना विचार व्यक्त किया । उन्होंने सभी हितधारकों से सक्रिय सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने निम्न मुद्दों पर चर्चा की

टिप्पणियां	**बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
i) **राज्य में बैंकों की बुनियादी समस्या पर चिंता व्यक्त किया एवं कहा की सरकार बैंकों को आवश्यक सहयोग देगी**	--	**झारखण्ड सरकार**
ii) **प्रधानमंत्री जन धन योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर , प्रखण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर**		**झारखण्ड सरकार/सभी बैंक**

पर उत्साहबर्धक नही है		
iii) **बैंकिंग राज्य के सम्पूर्ण विकास के लिए एक आवश्यक टूल है। बैंकों से आग्रह किया कि वे लोगों को बेहतर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए जरूरी माहौल बनाए।**	--	सभी बैंक
iv) **उन्होंने कहा की डी एल सी सी एवं बी एल सी सी की न तो बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है और न ही इनकी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है**	**सभी जिलों के उपायुक्त एवं अग्रणी जिला प्रबंधक , इस विषय पर उचित अनुपालन सुनिश्चित करे ।**	**राज्य सरकार / अग्रणी जिला के दायित्व वाले सभी बैंक**
v) **राज्य के बैंकों में बढ़ते एन पी ए पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक शाखाएं लोन देते समय credit worthiness का उचित ध्यान रखें , रेगुलर फॉलो अप करें । सभी जिलों में सर्टिफिकेट अधिकारी बहाल किया गया है लेकिन वसूली का कार्य नही हो पा रहा है । क्योंकि उन्हें बहुत सारे बिभागों का संयुक्त-प्रभार दिया गया है, जिसके चलते वे सर्टिफिकेट केसों पर ध्यान नहीं दे पाते ।इस कार्य हेतु समर्पित(Dedicated) सर्टिफिकेट अधिकारी का पदस्थापन की**	**राज्य सरकार एवं समस्त बैंक इसके कार्यान्वयन हेतु संभावित कार्रवाई करें**	**राज्य सरकार /समस्त बैंक**

आवश्यकता है । **vi) झारखंड में एन बी एफ सी का ज्यादा सक्रिय है। बैंक यदि आम जनता को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है तो एन बी एफ़ सी की भूमिका स्वत: ही कम होने लगेगा ।** **vii) एस एल बी सी द्वारा प्रस्तावित रोडमैप का अनुपालन राज्य एवं बैंकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा** **viii) प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत्त खाताधारकों का उचित पहचान करना, खातों का नियमित संचालन करना एवं इन खाता धारकों योजना की सही जानकारी प्रदान करना** ix) **राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नही दिया जा रहा है। किसान मित्र का मदद ले कर सभी किसानों को के सी सी जारी किया जाए।**	**समस्त बैंक आवश्यक एवं उचित अनुपालन सुनिश्चित करें ।** **समस्त स्टेक होल्डर रोड मैप का अनुपालन सुनिश्चित करें** **सभी बैंक अनुपालन सुनिश्चित करें ।** -- **सभी स्टेक होल्डर अनुपालन सुनिश्चित करें ।**	सभी बैंक **समस्त बैंक /झारखण्ड सरकार/नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक** **समस्त बैंक** **राज्य सरकार/समस्त बैंक/नाबार्ड**

श्री सौरभ सिन्हा,मुख्य महाप्रबन्धक,भारतीय रिजर्व बैंक का संबोधन

श्री सिन्हा ने 50वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने कहा कि झारखंड के नई सरकार से बैंकों को बहुत उम्मीद है। यदि हमें सरकार का पूर्ण सहयोग मिला तो हम राज्य के विकास के लिए हर कोशिश करेंगें । उन्होने यह भी कहा की सरकार बैंकों के सहयोग से 14 वर्ष की पुरानी लेकिन मजबूत स्थिति में वापस आ सकती है । उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) एम एस ई ऋण एम एस ई का ऋण संवितरण में पूर्व वर्ष के 65% के विकास के सापेक्ष अब तक की उपलब्धि मात्र 48% है। झारखण्ड जैसे खान-खनिजों से भरपुर राज्य के लिए यह अत्यंत निराशाजनक है। झारखंड में एम एस ई के विकास हेतु पूर्ण अवसर उपलब्ध है। इस राज्य के लिए रूपये 5500 करोड़ का लक्ष्य भी एक आसान लक्ष्य है। 2) पिछले वर्ष के दौरान सी जी टी एम एस ई के तहत्त कवरेज काफी अच्छा रहा लेकिन इस वर्ष इस क्षेत्र में उत्साहजनक वृद्धि नही हुई	राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जिला को निर्देश जारी किया जा सकता हैं कि पी एम ई जी पी के लंबित केसों का तुरंत निपटान किया जाए। Task Force के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व बैकर्स का एक समूह प्रत्येक आवेदन का ड्यू -डिलिजेन्स कर,उसका तुरंत निपटान हेतु समाधान कर सकते हैं । इन आवेदनों के निपटान हेतु समय सीमा का भी निर्धारण किया जाए	उद्योग बिभाग,राज्य सरकार/ समस्त बैंक -- राज्य सरकार/ समस्त बैंक

है। 2) प्रत्येक जिला की भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार वहाँ विशेष उद्योग खुलते हैं एवं उनके भिन्न-भिन्न पैरामीटर होते है। इस आधार पर एक समिति बना कर नये उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करना चाहिए।		समस्त बैंक/अन्य हितधारक
2) भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही एम एस एम ई सेक्टर के विकास हेतु एक नया प्रोडक्ट बाजार में ले कर आ रही है। इसके लांच से एम एस एम के विकास को गति मिलेगी एवं इस क्षेत्र में बेहतर ऋण संवितरण संभव हो सकेगा।		भारतीय रिजर्भ बैंक

श्री आर एस पोद्दार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त का संबोधन

श्री पोद्दार ने 50वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किये गये समस्त सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक महत्पूर्ण सहयोगी है। अत: सरकार के विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु उनकी सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) एम एस ई के क्षेत्र में ऋण का संवितरण - एम एस ई के क्षेत्र में क्रेडिट का संवितरण सकारात्मक नही है। सभी बैंक इसमें वृद्धि करने हेतु सहयोग करें।	-- --	उद्योग बिभाग,राज्य सरकार/ समस्त बैंक

यह प्रशंसनीय है कि एस एल बी सी अपनी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करती है एवं एस एल बी सी लिये गये निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई भी गंभीरतापूर्वक करती है लेकिन जिला स्तर पर डी एल सी सी का एवं प्रखण्ड स्तर पर बी एल सी सी बैठकों का आयोजन नियमित रूप से नही किया जाता है। एस एल बी सी एवं राज्य सरकार मिलकर डी एल सी सी एवं बी एल सी सी को मजबूत करे। राज्य सरकार आवश्यक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि एस एल बी सी के पैटर्न पर जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर भी बैठक आयोजित किया जाए। डी एल सी सी / बी एल बी सी को और अधिक सार्थक और संरचित किये जाने की आवश्यकता है।		**झारखण्ड सरकार /आर बी आई/ अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी जिलों के उपायुक्त |**
3) **राज्य के विकास हेतु सरकार एवं बैंक पार्टनर हैं एवं राज्य सरकार बैंकों के साथ मिलकर पार्टनरशीप के रूप में कार्य करेगी।**		**राज्य सरकार/ समस्त बैंक**
4)एस एच जी ग्रूप का क्रेडिट लिंकेज को गति देने की आवश्यकता है।		सभी बैंक/NABARD/JSLPS
5) अब सब्सिडी रेजिम को समाप्त किया जा रहा है एवं इन्ट्रेस्ट		

सववेन्शन को लागू किया जा रहा है। इससे ग्राहकों का क्रेडिट वर्दिनेश बढ़ेगा एवं बैंक के ऋण संवितरण में वृद्धि होगी।		
6) कौशल विकास मिशन 2015 के तहत्त 15 लाख ग्रामीण युवकों का कौशल विकास करना है। बैंकों से अनुरोध है कि इस कार्य में पूर्ण सहयोग दें। वैसे तो आरसेट्टी एवं रूडसेट्टी अच्छा कार्य कर रहे है फिर भी इन संस्थानों को और अधिक मजबूत किये जाने की आवश्यकता है।		सभी बैंक/RSETI/ग्रामीण विकास बिभाग, झारखण्ड सरकार
8) राज्य में 47 नये प्रखण्ड खुले है। बैंकों से अनुरोध है कि सभी प्रखण्ड हेडक्वार्टर में बैंक शाखा खोलें एवं बीसी/बीसीए की सहायता से उन सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करें जहां बैंक की शाखाएं नही खोली जा सकती है।		सभी बैंक

श्री राजीव गौबा, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का संबोधन

श्री गौबा ने 50वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत्त 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को हार्दिक बधाई दिया एवं निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	**बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
1) वित्तीय समावेशन : क्रिसिल के सर्वे के अनुसार वित्तीय समावेशन में 100 के कुल स्कोर में देश को 40 अंक प्राप्त होते है एवं झारखण्ड राज्य में स्थिति और भी	--	--
	--	--

खराब होगा। हालांकि राज्य में बैंको ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत्त खाता खोलने के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है लेकिन खाता खोलना ही वित्तीय समावेशन को पूर्ण नही करता है। वित्तीय समावेशन के तहत्त हमें उन खाता धारकों को सशक्त करना भी है एवं उन्हें समस्त बैंकिग सेवाओं का पूर्ण कवरेज मिलना चाहिए। राज्य सरकार एवं बैंक सुनिश्चित करें कि बीमा, वृद्धा पेंशन एवं अन्य सुविधाएं भी उनके इन्हीं खातों से दिया जाए। उन्होंने इन खातों की आधार लिंक कराने की जरुरत पर जोर दिया |	--	राज्य सरकार/ समस्त बैंक
2) राज्य में मनी लेंडर अब भी सक्रिय है। वित्तीय समावेशन के तहत्त बैंक एवं सरकार मिल कर कार्य करें एवं विशेषकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आम निरीह गरीब जनता को बैंक से जोड़ कर मनी लेंडर को निष्क्रिय किया जा सकता है।		राज्य सरकार/ समस्त बैंक
3) बैंक आधुनिक तकनीक , सूचना प्रौद्योगिकी बी सी/बी सी ए/माइक्रो ए टी एम का प्रयोग कर बैंकिंग को डोर - स्टेप तक पहुंचाएं । आज भी गढ़वा, चतरा, गिरिडीह आदि जिलों में बैंक की कम शाखाएं है। राष्ट्रीय औसत 15,000		समस्त बैंक/जिला प्रशासन

जनसंख्या प्रति बैंक शाखा के सापेक्ष में इन जिलों का औसत बहुत ज्यादा है और फलत: इन जिलों में बैंक शाखाओं का नेटवर्क बढाना होगा|		
4) वित्तीय साक्षरता बैंक वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान दें।		समस्त बैंक/नाबार्ड
5) एस एल बी सी द्वारा तैयार किया गया रोडमैप दस्तावेज : उन्होंने कहा कि एस एल बी सी ने जो रोडमैप तैयार किया है, वह एक उत्कृष्ट दस्तावेज है और उसमें राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार, बैंक एवं समस्त स्टेक होल्डर इसका कार्यान्वयन करें।		राज्य सरकार/जिला प्रशासन/समस्त बैंक/नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक
6) एस एल बी सी द्वारा प्रायोजित कार्यकलाप एवं सभाओं में निजी बैंको की सहभागिता को बढाने हेतु आबश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया |		एस एल बी सी / निजी क्षेत्र के बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक
7) राज्य सरकार का सहयोग : उन्होंने कहा कि हम बैंको की समस्या से अवगत है। जहां तक कानून एवं विधि व्यवस्था, बिजली, लोन की वसूली आदि की बात		राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक

है ,इन क्षेत्र में राज्य सरकार सम्पूर्ण सहयोग देगी एवं इसके लिए हम सभी बैंको एवं एस एल बी सी को आश्वस्त करते है।		

श्री सी पी सिंह, माननीय शहरी विकास मंत्री , झारखण्ड सरकार का संबोधन : श्री सिंह ने 50वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की सराहना करते हुए कहा कि आज की बैंकिग के क्षेत्र में क्रांति के कारण बैंकिंग आसान एवं सरल हो गया है। उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) बैंक सभी पात्र छात्रों को शिक्षा ऋण मुहैया कराने का प्रयास करें।		**समस्त बैंक**
2) निजी क्षेत्र के बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की तरह आम जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें एवं आम जनता का विश्वास जीते।		निजी क्षेत्र के बैंक
3) बैंक वैसे तो बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है लेकिन बैंकों से अनुरोध हैं कि वे आम जनता को उत्कृष्ट बैंकिग सेवाए प्रदान करें।		**समस्त बैंक**

श्री सिंह ने निष्कर्षत: कहा कि बैंक आर्थिक विकास का रीढ़ है एवं आम जनता को बैंको से जोड़ कर बैंक राज्य के विकास को गति प्रदान कर सकते हैं।

श्री रघुवर दास, माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार का संबोधन : श्री सिंह ने 50वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की सराहना करते हुए कहा कि आज की बैंकिग के क्षेत्र में क्रांति के कारण बैंकिंग आसान एवं सरल हो गया है। उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) बैंको की एक महत्वपूर्ण समस्या है राज्य में खराब कानून व्यवस्था। हमारी सरकार की भी यह प्राथमिकता है और छः माह के अन्दर कानून व्यवस्था को बेहतर कर देंगे ।		राज्य सरकार
2) रांची में एस एल बी सी, प्रमुख बैंक के आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटित किया जाना : छः माह के अंदर भूमि उपलब्ध करा दिया जाएगा।		राज्य सरकार/समस्त बैंक/एस एल बी सी
3) झारखण्ड राज्य में 42 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य के आर्थिक विकास हेतु बैंक अपना महत्वपूर्ण योगदान दें । हालांकि प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत्त खोले जाने वाले खातों हेतु बैंको को हार्दिक बधाई दिया एवं बैंकों से पुनः अनुरोध किया कि इन खातों के संचालन हेतु बैंक साक्षरता अभियान चलाएं। आवश्यक हो तो कैम्प मोड में शेष लोगों का खाता खोलें एवं उस अवसर पर वित्तीय साक्षरता भी प्रदान की जाए। "प्रधान मंत्री जन धन योजना"		राज्य सरकार/समस्त बैंक/एस एल बी सी

के कार्यान्वयन के तहत्त झारखण्ड के बैंक देश में एक रिकार्ड स्थापित करे। इससे आम आदमी देश की विकास से तो जूड़ेगा ही साथ में साहूकार का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा।		
4) कौशल विकास योजना - राज्य सरकार की कौशल विकास योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,विशेषज्ञ आदि को भी शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए बैंको का सहयोग हेतु अनुरोध भी किया।		सभी बैंक/कौशल विकास बिभाग,झारखण्ड सरकार
5) उन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान में बैंको के सहयोग की अपेक्षा की		सभी बैंक
6) उन्होंने 2 प्रतिशत सी एस आर से एक ट्रस्ट बनाने हेतु अनुरोध किया और कहा कि राज्य सरकार बैंकों के सी एस आर का 2 प्रतिशत से एक ट्रस्ट बनाना चाहती है जिसका उपयोग राज्य के समग्र विकास के लिए किया जाएगा ।		सभी बैंक
7) सी एन टी/एस पी टी अधिनियम : इस अधिनियम के मौजूदा शर्तो के अनुसार झारखण्ड राज्य के नौजवान बैंक से शिक्षा ऋण, मोर्टगेज ऋण आदि नही ले पा रहे है। इसमें आवश्यक सुधार की जरुरत महसूस की जा रही है|		झारखण्ड सरकार |
8) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत्त चयनित गांवो में बैंक के शाखा खोले जाने हेतु अनुरोध किया		सांसद एवं बैंक|

9) उन्होने कहा कि झारखण्ड के बैंकों वर्तमान ऋण -जमा अनुपात 61 प्रतिशत है इसको बढ़ाकर कम से कम 65-66 प्रतिशत किया जाए और इसे बढ़ाने के लिए निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को ऋण प्रदान किया जाए ।		सभी बैंक ।
10) राज्य में 40 लाख किसान है जबकि मात्र 15 लाख लोगो को ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। यह चिन्ता का विषय है। इसमें बढ़ोतरी किया जाए ।		सभी बैंक एवं कृषि बिभाग,झारखण्ड सरकार।
11) राज्य में केवल 4.5 लाख किसानों को ही रूपे कार्ड जारी किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि शिविर लगा कर रूपे कार्ड दिया जाए ।		सभी बैंक
12) उन्होंने राज्य के विकास हेतु 03 तंत्रों 1. उद्योग 2. कृषि एवं 3. आई टी विभाग को मजबूत किये जाने पर बल दिया एवं बैंकों से अनुरोध किया कि इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें ताकि हम विकास के मामलें में महाराष्ट्र एवं गुजरात की बराबरी कर सकें।		सभी बैंक एवं झारखण्ड सरकार

49वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

तत्पश्चात् श्री आलोक प्रकाश यादव, उप महाप्रबंधक , एस एल बी सी ने सभा में चर्चा की जाने वाली विन्दुओं का क्रमवार प्रस्तुतीकरण किया।

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
<u>कार्यसूची सं. 1</u> <u>ऋण-जमा अनुपात</u> 1. राज्य का ऋण - जमा अनुपात 61.76 प्रतिशत है जो देश के ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है। तथापि राज्य के कुछ जिलों का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है जबकि कुछ जिलों जैसे कि गुमला,सिमडेगा,चतरा और सिंहभूम का ऋण जमा-अनुपात 30 प्रतिशत से भी कम है। राज्य के दोनों ग्रामीण बैंकों(R.R.B) का ऋण-जमा अनुपात बढ़ा है जबकि 15 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको एवं 08 निजी क्षेत्र के बैंकों का ऋण -जमा अनुपात घटा है। हालांकि यदि 09 माह के जमा और ऋण का अध्ययन किया जाए तो यह पाया जाता है कि इस अवधि में प्राप्त जमाओं का 93 प्रतिशत ऋण के रूप में संवितरत किया गया है। राज्य के 10 पी एस बी, 5 निजी क्षेत्र के बैंक और 02 आर आर बी का का सी डी अनुपात बढ़ा है, जबकि 10 पी एस बी एवं 8 निजी क्षेत्र के बैंकों का घटा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण -जमा अनुपात 52 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ है जबकि निजी क्षेत्र के बैंको का ऋण-जमा अनुपात	कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिले का अग्रणी जिला प्रबंधक इसके बढ़ोतरी हेतु आवश्यक ध्यान दें एवं कम सीडी रेश्यों वाले बैंक भी इसे बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं एवं चर्चित योजनाओं के तहत्त ऋण में वृद्धि करें।	सभी बैंक/अग्रणी जिला प्रबंधक/एस एल बी सी

77 प्रतिशत से घटकर 68 प्रतिशत हुआ है और आर आर बी का ऋण -जमा अनुपात 39 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हुआ है। **<u>कार्यसूची संख्या - 2</u>** **<u>वार्षिक ऋण योजना</u>** इस योजना के तहत्त हमारा निष्पादन सोचनीय है। पिछले वर्ष के 53 प्रतिशत की उपलब्धि की तुलना में इस वर्ष मात्र 52.26 प्रतिशत की ही उपलब्धि हो पाई है। हालांकि इसकी समीक्षा प्री-एस एल बी सी बैठक के दौरान की गई थी जिसमें निम्न विन्दु उजागर हुए है: - **1 ज्यादा ध्यान पी एम डी जे वाई पर केंद्रित होना** **2. पिछली तिमाही के दौरान लोक सभा चुनाव का होना** **3. अच्छे उधारकर्त्ता का नही होना** **4. वसूली की स्थिति का अच्छा नही होना** **5. नये पात्र उधारकर्त्ता का नही होना** **6. भूमि अभिलेखों का डिजिटीकरण नही होना** **7. आवास ऋण में कम वृद्धि का होना** **8. डी आर आई योजना के तहत्त कम ऋण का संवितरण। इस**		

योजना के तहत्त नेट क्रेडिट का केवल .05 प्रतिशत ही ऋण संवितरित किया गया है। **9. हालांकि एस एच जी योजना के तहत्त उपलब्धि सराहनीय है फिर भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। इस योजना के तहत्त अनुदान राशि 1.32 करोड़ है जबकि क्रेडिट संवितरण की राशि 13.34 करोड़ है।**		

आगे की कार्यसूचि की पस्तुतिकरण श्री अंजन मोइत्रा ,वरिष्ठ प्रबंधक, एस.एल.बी.सी द्वारा किया गया ,

<u>कार्यसूची सं. - 3</u> **<u>प्रधानमंत्री जन धन योजना/वित्तीय समावेशन</u>** इस विषय पर श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, मिशन डायरेकटर ,प्रधानमंत्री जन धन योजना, एवं मुख्य सचिव,सुचना तकनीक, झारखण्ड सरकार , सभा की दृष्टिआकर्षण करते हुए बताया की यद्यपि इस योजना के तहत्त हमारी राज्य की उपलब्धि सराहनीय है लेकिन अभी निम्न कार्य किये जाने की आवश्यकता है :- **1.** एस एस ए को पूर्णत: सक्रीय किये जाने की आवश्यकता है। अभी तक ऑन -लाईन बी सी की पूर्णरूप से शुरूआत नही हुई है। इन केन्द्रों को ई-के वाई सी, माईक्रो ए टी एम, आधार आधारित पेमेन्ट के लिए सक्षम बनाने की आबश्यकता है ता की सरकार द्वारा अदूर भविष्य में दिए जाने वाली सभी अनुदान का भुगतान इन		समस्त बैंक/राज्य सरकार/बी एस एन एल

केन्द्रों के द्वारा किया जा सके | इस कार्य में बी एस एन एल के सहयोग की आवश्यकता होगी।		
2. इस विषय पर सभा द्वारा यह निर्णय लिया की सभी बैंकों ने **S.S.A** में स्थित अपनी **BC/BCA** की निरिक्षण,**SLBC** द्वारा निर्धारित **format** के अनुसार दि:**25.02.15** तक सम्पूर्ण कर लेंगे|		सभी बैंक
3. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत्त खोले गये सभी खातों में पासबुक जारी नही किया गया है। इसे शिविर लगाकर दिया जाना चाहिए। और यह शिविर सभी शाखा स्तर पर हर सप्ताह, शनिवार को लगाया जाय		सभी बैंक
4.प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत्त खोले गये सभी खातों में आवश्यक रूप से रुपे कार्ड जारी करना है लेकिन अभी तक सभी खाता धारकों को रूपे कार्ड जारी नही किया गया है। बहुत ज्यादा संख्या में रूपे कार्ड शाखाओं में अनडेलिवर्ड पाया गया है, यह एक सेक्योरिटी का भी मामला है। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि जल्द -जल्द से ग्राहकों को रूपे कार्ड जारी किया जाए। इस विषय पर श्री एन एन सिन्हा ने कहा कि रूपे कार्ड का भरपुर प्रचार किया जाए।		सभी बैंक
5. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत्त खोले गये सभी खातों में आधार सीडिंग सुनिस्श्चित किया जाय - इन खातो में अभी तक मात्र 46 प्रतिशत खातों में ही आधार सीडिंग किया गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर, झारखण्ड सरकार द्वारा दिए जाने वाली बिभिन्न अनुदान योजना के लाभुकों के बैंक खाते में आधार सीडिंग सुनिश्चित किया जाय | झारखण्ड		सभी बैंक,अग्रणी जिला बैंक

सरकार के सभी बिभागों की जिलास्तरीय कर्मचारी , **LDM** को लाभुकों की आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या, निहित प्रपत्र पर उपलब्ध कराएगी|		
6. श्री सिन्हा ने सभी बैंकों से यह आग्रह किया की, वे **DBT Cell** द्वारा निर्मित **Best Practice for BC Operation** को अपनाएं|		सभी बैंक
7. श्री सिन्हा ने सभी बैंकों से यह आग्रह किया की, **WSHG** के ऋण-संयोजन के लिए लंबित सभी आवेदनों पर दि:**15.03.15** तक ऋण की स्वीकृति प्रदान करें|		सभी बैंक
महाप्रबंधक - एस एल बी सी का सुझाव - (क) इसके लिए एक समय-सीमा तय किया जाए		सभी बैंक
(ख) कैम्प मोड में आधार सीडिंग किया जाए		
ग) D.F.S,MOF,**भारत सरकार एवं** I.B.A **इन खाता धारकों को रूपये 5,000/- का ओवर-ड्राफ्ट देने हेतु एक Common Guidelines का तैयारी कर सभी बैंकों को सूचित करें।**		DFS,MOF,GOI.
(घ) भारत सरकार , PMJDY **योजना के तर्ज पर , सभी बैंक खातों में आधार सीडिंग के लिये EXTENSIVE MEDIA CAMPAIGN का शुरुआत करें|**		
5. बैंक रहित, कम बैंक वाले क्षेत्र और सांसद ग्राम योजना के तहत्त तय गांवों में बैंक शाखा खोलने हेतु B.S.N.L **लिज्ड लाईन**(Leased		B.S.N.L एवं झारखण्ड उर्जा वितरण निगम

Line) **की** connectivity **और पर्याप्त बिजली(**Power**) आपूर्ति की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु बी एस एन एल और झारखण्ड राज्य उर्जा विकास निगम से सहयोग की अपेक्षा है।**		
6.**बी सी /बीसीए को सक्रिय किया जाना एवं इनका औचक निरीक्षण किया जाना - इस विषय पर श्री एन एन सिन्हा ने कहा कि अभी तक इस तंत्र को सक्रीय नही किया गया है और न ही बीसी/बीसीए का 100 प्रतिशत औचक निरीक्षण किया गया है। झारखण्ड ग्रामीण बेंक के 87 बीसी/बीसीए का अब तक निरीक्षण नही किया गया है।**		सभी बैंक एवं D.L.I.C
सभा में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा इस कार्य के लिए तय समय -सीमा - 25.02.2015 को निर्धारित किया गया|		
इस विषय पर श्री मिहिर कुमार ने कहा कि,		
क. बी सी /बी सी ए के लिए एक मानक मॉडल एवं मानक दस्तावेज तैयार किया जाए, जिस पर सभा में आम सहमति बनी।		ग्रामीण विकास बिभाग,झारखण्ड सरकार/DBT Cell/समस्त बैंक
ख. जल्द से जल्द PMJDY **खातों में** BC/BCA **द्वारा भुगतान प्रारंभ किया जाय |**		सभी बैंक
7.**श्री बृज लाल , अध्यक्ष झारखण्ड ग्रामीण बैंक ने** PMJDY **योजना के तहत दिये सने वाली रू** 5000/- **की** O.D **खातों की पात्रता एवं स्वीकृत राशि निर्धारण हेतु,** DFS MOF,GOI **द्वारा एक दिशानिर्देश जारी करने की अनुरोध किया|**		DFS,MOF,GOI/सभी बैंक
8. **वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन - भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार**		सभी बैंक

ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षारता शिविर लगाकर आम जनता को बैंकिंग से संबंधित जागरूकता पैदा करना है। लेकिन यह कार्य नही हो रहा है। इस विषय पर महाप्रबंधक-एस एल बी सी के अनुरोध पर सभा में निर्णय लिया गया कि वित्तीय साक्षरता हेतु सापताहिक कैम्प लगाया जाए एवं सभी ने सर्वसम्मती से शनिवार का दिन तय किया । 9. PMJDY **खातों में देय बिमा की पात्रता जरी रखने हेतु ,** RUPAY **कार्ड को हर एक 45 दिनों के अंतराल में ,आबश्यक संचालन का जो प्रावधान रखा गया है उसे और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस पर सभी स्टेक होल्डर ने सर्वसम्मति से पारित किया।** **9. डी बी टी एल की पहल योजना के तहत बैंक खातों में आधार सीडिंग हेतु सभी शाखा स्तर पर आबश्यक कदम उठाया जाय जैसा की ड्रॉप-बॉक्स इत्यादि, साथ ही सभी** Oil Marketing Company **से आग्रह किया गया की वें आधार सीडिंग हेतु निहित प्रपत्र में** LIST **की** SOFT COPY , LDM **को उपलब्ध कराएं|**		एस.एल.बी,सी/DFS MOF GOI OIL MARKETING COMPANIES/सभी बैंक
<u>कार्यसूची संख्या - 4 वसूली</u> **1. एल एस एल बी सी ने प्रस्ताव दिया कि जिला स्तर पर समर्पित सर्टिफिकेट ऑफिसर की बहाली हो और उन्हें इस कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नही दिया जाए।**	**राज्य सरकार ने सहमति दी**	**राज्य सरकार**

2. एस एल बी सी ने प्रस्ताव दिया कि झारखण्ड राज्य में डी.आर. टी की एक और शाखा खोला जाए। एवं झारखण्ड राज्य में डी.आर.टी कि अपीलीय ट्रिबुनल, जो कि अभी इलाहाबाद में स्थित है, झारखण्ड राज्य में उसकी एक शाखा कि स्थापना किया जाय| इस विषय पर महाप्रबंधक- एस एल बी सी ने कहा कि मामलों के निष्पादन एवं लंबित मामलों में बड़ा अंतर है,अभी तक 1800 मामले पेंडिंग है। इस पर श्री मिहिर कुमार ने कहा कि इसका प्रस्ताव वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा जाए ।		**भारतीय रिजर्भ बैंक,SLBC एवं DFS,MOF,GOI.**
3. एस एल बी सी ने प्रस्ताव दिया कि सरफैसी के तहत्त मामलों के निपटान में जिला मजिस्ट्रेट के पास लंबा समय लग जाता है। सरफैसी मामले के निपटान में प्रशासनिक सहयोग और मोर्टगेज संपति का अधिकार प्राप्त करने के लिए जिला उपायुक्तों के पास लम्वित आवेदनों कि तुरंत निष्पादन हो|		झारखण्ड सरकार
4. एस एल बी सी ने पी डी आर अधिनियम में आवश्यक संशोधन कि बहुत दिनों से लंबित प्रस्ताव हेतु निम्नलिखित दृष्टिआकर्षण किया- राज्य सरकार -द्वारा एम पी और यू पी वसूली अधिनियम के	**इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया**	झारखण्ड सरकार

तर्ज पर जो एक मॉडल पी डी आर अधिनियम भी है , के अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाय । (नोट :<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u>- जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा Certificate Case दाखिल करते समय, अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर रिकवरी की , राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान किया जाता है, एवं रिकवरी की राशि से ही रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है ।(		
<u>कार्य सूची संख्या - 6 - ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान</u> **राज्य में 24 आरसेट्टी एवं 01 रूडसेट्टी कार्यरत है लेकिन इनके अभी तक मात्र 03 का भवन निर्माण का शुरू हुआ है। इसके लिए बैंक,राज्य सरकार एवं एस एल बी सी उचित कार्रवाई करें।** **सिली जिला में एक आरसेटटी एस बी आई को बनाना है , लेकिन इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से को पैसा आना चाहिए वह अब तक आवंटित नही किया गया है। सरकार के सहयोग की अपेक्षा है**		RSETI के सम्बंधित प्रायोजक बैंक/ग्रामीण विकास बिभाग झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार
कार्यसूची संख्या - 7 - ग्रामीण बैंक के निदेशक बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि(उपायुक्त) की उपस्थित न होना - एस एल बी सी ने सभा को सूचित किया कि उपरोक्त बैठकों में	**मुख्य सचिव , सांस्थिक वित्त बिभाग , झारखण्ड सरकार ने यह आश्वासन दिया कि आगे की बैठकों में उपायुक्तों कि उपस्थिति सुनिश्चित की**	**राज्य सरकार**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि भाग नही लेते है, जिसके कारण बैठक की गंभीरता नही रह पाती ।	जाएगी ।	
कार्यसूची सं. - 8 एस एच जी क्रेडिट लिंकेज - राज्य सरकार के प्रतिनिधि श्री एन एन सिन्हा ने कहा कि 2600 एस एच जी खातों का क्रेडिट लिंकेज का कार्य लंबित है। लिंकेज का दर भी धीमा है । इस कार्य के लिए एक समय सीमा तय किये जाने की आवश्यकता है।	इस कार्य के लिए तय समय सीमा - 15.03.2015	समस्त बैंक
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय	अन्य विषय नही होने के कारण चर्चा को समाप्त कर दिया गया ।	
एस एल बी सी द्वारा तैयार किया गया - "झारखण्ड के समेकित विकास के लिये बैंकिंग कि बिस्तृत कार्य योजना एवं सुझाव"		
झारखण्ड के समग्र एवं समेकित विकास के लिए एस एल बी सी ने बैंकिंग के लिए एक रोडमैप तैयार किया है जिसकी सभा ने सराहना की एवं सर्वसम्मती से स्वीकार किया। रोडमैप की प्रति सभी स्टेक होल्डर को वितरित किया गया है।		
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति , झारखण्ड कि अगली त्रैमासिक समीक्षा बैठक,(31.03.15 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये) कि निर्धारित तिथि दिनांक: 14 मइ,2015 , कि घोषणा कि गइ ।		

श्री एस.के.सिंह उप-महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक ने सभा के अंत में बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को उनकी सक्रीय सहभागिता के लिये धन्यवाद ज्ञापन किया एवं उसके उपरांत सभा कि समाप्ति कि घोषणा कि गयी ।